संख्या-360 /2024/1722/22-2-2022-17(1673)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षकए
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायेंए
उत्तर प्रदेशए लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 दिसम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरवल उर्फ विधायक पुत्र श्री जनवेद सिंह निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21667/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022) दिनांक-04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरवल उर्फ विधायक पुत्र श्री जनवेद सिंह, भानुपुर पगना, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का निवासी है। बन्दी ने जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 08.11.2005 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लकड़ी से गला दबाकर 05 वर्षीय बालक अतुल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-124/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/कोर्ट संख्या-05, इटावा के आदेश दिनांक 11.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2020 तक अपरिहार 15 वर्ष, 23 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 04 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 08.11.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लकड़ी से गला दबाकर 05 वर्षीय बालक अतुल की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वीरवल उर्फ विधायक पुत्र श्री जनवेद सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरवल उर्फ विधायक (बंदी संख्या-22877) पुत्र श्री जनवेद सिंह निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्टए 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-360/2024/1722(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-360/2024/1722/22-2-2022-17(1673)/2022

दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरवल उर्फ विधायक पुत्र श्री जनवेद सिंह, भानुपुर पगना, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का निवासी है। बन्दी ने जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 08.11.2005 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लकड़ी से गला दबाकर 05 वर्षीय बालक अतुल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-124/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/कोर्ट संख्या-05, इटावा के आदेश दिनांक 11.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2020 तक अपरिहार 15 वर्ष, 23 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 04 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 08.11.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लकड़ी से गला दबाकर 05 वर्षीय बालक अतुल की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वीरवल उर्फ विधायक पुत्र श्री जनवेद सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।